कृपया प्रकाशनार्थ - **11 मई 2009**

भाजपा नेता व पूर्व केंद्रिय मंत्री श्री राम नाईक ने सोमवार, दि. 11 मई 2009 को मुंबई में पत्रकार संमेलन में किया वक्तव्य

मेट्रो रेल को समर्थन; मगर कारशेड का विरोध

मुंबई, सोमवार : मुंबई में मेट्रो रेल हो इसलिए मेरा पुरा समर्थन है, किंतु इसके लिए चारकोप में कारशेड बनाना मुझे कतई मंजूर नहीं क्योंकि इस कारशेड से हजारो नागरिक बेघर होंगे; ऐसा अभिमत भाजपा नेता व पूर्व केंद्रिय मंत्री श्री. राम नाईक ने मेट्रो रेल के संदर्भ में आयोजित जाहीर सुनवाई में व्यक्त किया. इस सुनवाई के बाद पत्रकार परिषद को संबोधित करते समय श्री. नाईक ने यह जानकारी दी.

आम मुंबईवासी की तरह श्री. राम नाईक भी रेल यात्रा थोडी बहुत सुखमय हो इसलिए मेट्रो रेल प्रकल्प के पक्ष में है. मगर इस रेल्वे की कारशेड के लिए चारकोप में गणेश नगर, संजय नगर, लालजीपाडा, गांधी नगर, एकता नगर, तथा जनता कालनी के हजारो लोग बेघर हो यह मानवधर्म के विरोध में है; इसलिए इस कारशेड की नियोजित जगह बदलनी चाहीए, ऐसी स्पष्ट भूमिका श्री. नाईक ने सुनवाई के समय अपनायी. श्री राम नाईक ने पाँच बार उत्तर मुंबई का लोकसभा में प्रतिनिधीत्व किया है. इसी उत्तर मुंबई का चारकोप हिस्सा है. श्री राम नाईक रेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रह चूके है और उन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली में मेट्रो रेल्वे बनी. जाहीर है; वह इस विषय के अनेकानेक पैलूओं से सुपरिचित है.

चारकोप में नियोजित कारशेड की जगह पर 14,000 परिवार बसे हैं. इसी जमीन पर कई मान्यताप्राप्त स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर तथा दुकाने व उद्योग भी है. इन सबको विस्थापित करने के बजाय चारकोप-दहिसर क्षेत्र में अन्य जगह रिक्त क्षेत्र पर कारशेड बनाने की माँग भी श्री नाईक ने सुनवाई के समय की. स्थानिक जनता का इस कारशेड को कडा विरोध है इसका एहसास भी श्री. नाईक ने दिलवाया.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारण के अधिकारीओं का जनता की न सुनते हुए मनमानी से प्रकल्प का काम शुरु करने का रवैया ध्यान आते ही हजारो लोगों की स्वाक्षरी का आवेदन श्री राम नाईक ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. विलासराव देशनुख को 11 सितंबर 2008 को दिया. विषय की गंभीरता देखते हुए उन्होंने श्री. विलासराव को तीन स्मरणपत्र भी भेजे. बाद में सत्ता पर आए मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण से भी श्री. नाईक ने 19 दिसंबर 2008 तथा 18 जनवरी व 4 फरवरी 2009 को पत्र लिखकर चर्चा के लिए समय की माँग की. प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को भी दो बार प्रार्थना पत्र भेजे. किंतु इन तिनों ने किसी भी पत्र का जबाब नहीं दिया. सार्वजनिक हित के प्रकल्प के संबंध में भी यह सरकार जनता से संवाद करना नहीं चाहती यह इससे जाहीर है. मगर यह रवैया छोड कर बातचीत से मसला हल नहीं किया तो चारकोप में दुसरा 'सिंगूर' होगा ऐसा भी राम नाईक ने सुनवाई के समय कहा.

यह प्रकल्प निजि संस्थाओ द्वारा करवाया जाएगा. इसलिए मुंबई के सभी प्रकल्पबाधितों का पुनर्वसन कौनसी शर्तों के आधारपर किया जाएगा यह तय करके ही काम शुरु करना चाहिए अन्यथा प्रकल्प में बार-बार बाधाएँ आ सकती है, ऐसी सूचना भी इस समय श्री. नाईक ने दी. मेट्रो रेल के कारण कहाँ और कितने लोग बाधित होंगे इसका लोगों को सही अंदाजा आए इसलिए प्रत्यक्ष जमीनपर रेखांकन (Marking) हो ऐसा सुझाव भी श्री. नाईक ने दिया. मेट्रो रेल प्रकल्प कम खर्चे में हो इसलिए उसे ब्रॉड गेज बनाया जाए, उसका किराया भी आम आदमी दे सके इतनाही हो ऐसा आग्रह भी श्री नाईक ने रखा. फिलहाल की योजना के अनुसार प्रस्तावित किराया उपनगरीय रेल के चौगुना तो बेस्ट बस के किराए से दुगना है, आम आदमी यह बोझा नहीं उठा पाएगा. इसलिए मेट्रो रेल्वे के किराए पर महाराष्ट्र विधीमंडल का नियंत्रण हो ऐसी व्यवस्था रखने की सुझाव भी श्री नाईक ने दिया.

बार - बार टेंडर निकालने के बावजूद भी अब तक किसी ने भी मेट्रो रेल के लिए टेंडर नहीं भरें ऐसी खबरे अखबारों में आती रहती है. इस विषय में भी जनता को विश्वास में लेकर सरकार ने सत्य कहना चाहिए, ऐसा भी सुनवाई के समय श्री राम नाईक ने कहा.

(कार्यालय मंत्री)